



संख्या
76/82
मार्च 1982

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

मही दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/फाल्गुन 5, 1903

No. 34]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/PHALGUNA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे इस वाले अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य नियमाला

सार्वजनिक सूचना संख्या 10 आई०टी०सी० (पी०एन) /82

मही दिल्ली, 24 फरवरी, 1982

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय:—विदेशी आर्थिक सहयोग निधि जहन करार सं० आई०डी०पी०-11
मोर आई०डी०पी०-12 (दूर संचार परियोजना सं० 3 और 4
के अधीन माल और सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस दाते)।

नियिल संख्या-आई०पी०सी० 23 (26) /82—इक एवं तार महानिवेशालय की दूर संचार परियोजना सं० 3 और 4 की आयात आवश्यकताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आई०सी०एफ० जहन करार सं० आई०डी०पी०-11 और आई०डी०पी०-12 का येन 5.0 विलियन और येन 9.4 मिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 और 2 में वी गई हैं, उन्हें जासकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

मणि भारतीयस्वामी, मुख्य नियन्त्रक आयात नियंत्रण

परिशिष्ट 1

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 10 आई०टी०सी० (पी०एन) /82,
विलियन 24 फरवरी, 1982 का परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आई०सी०एफ०) द्वारा प्रदान किए गए दूर संचार परियोजना (3) के लिये येन 5.0 विलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस दाते।

खण्ड 1. सामान्य शर्तें

1(1) इक एवं तार महानिवेशालय की दूर संचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं को वित्तालय करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आई०सी०एफ०) द्वारा प्रदान किया 5.0 विलियन येन का जहन विकासपील देशों के लिए छुला है। तथनुसार, इस क्रेडिट के अधीन प्रधिप्राप्त की जाने वाली अनुबंध और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्दृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस जहन के अन्तर्गत पात्र ज्ञात देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी भूत्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिवेशालय, तकनीकी

विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रिटिक के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सी०) का मूल्य येन 5,600 मिलियन (लागत बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होता चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूपए में मूल्य, राजस्व विभाग (बीमा एक्स) द्वारा अधिवृच्छित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की नियम को प्रतिलिपि वर और मुख्य नियंत्रक आयात-नियात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78 प्राई०टी०सी० (पी०एन०)/७४ दिनांक ६ जून, १९७४ के पैरा-२ के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विवेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में विनियित मुद्रा विनियम दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक “जापानी येन अर्ण सं० प्राई०टी०सी०-११” प्रथम और द्वितीय प्रश्नय के लिए लाइसेंस में “एस/जेसी” कोट होगा। शी०सी०पी० एण्ड टी० की आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियात के पत्र में भी इसे दुहराया जाए। जिसकी एक प्रति विस भैतिलय, भार्यिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठाकृत की जारी चाहिए।

1(3) लागत बीमा भाड़ा के आधार पर केवल शी०सी०पी० एण्ड टी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) शी०सी०पी० एण्ड टी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रिटिक के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 5,600 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होता चाहिए जैसा कि कपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि शी०सी०पी० एण्ड टी० द्वारा आवेदन करने पर ३१-१२-१९८५ तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन भार्यिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रिटिक के अधीन वित बात किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिवेदित है।

1(7) विवेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रूपए में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही पार होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के अनुदेश अनुबन्ध १ में उल्लिखित दोषों में स्थित विवेशी संभरकों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर किए जाने चाहिए और ये आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से ४ महीने की अवधि के भीतर भार्यिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रूपए में भारत में देय होगा। “पक्के शादेशों” का भर्य विवेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस जारी द्वारा दिए गए उन क्रय आवेदनों से हैं जो विवेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विवेशी संभरक द्वारा द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विवेशी संभरकों के भारतीय अभिकरणों के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकरणों द्वारा पुष्टिकरण आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

1(9) भार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक मनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेकों के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से भार महीने के भीतर वित मंत्रान्तर, भार्यिक कार्य विभाग उल्लू०१०-१ अनुभाग को

नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के भावेश भार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो भार महीनों के भीतर आवेश भार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की नियम से ४ महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपकाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित मंत्रालय, भार्यिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), भारत ब्लाक, नई विस्तीर्ण को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार करने और अन्य निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाली एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रधिकृत व्यापारी और विवेशी प्राधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण डेकों में बैक गारंटी सत्य पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रूपय, अमा कराने आदि की स्वीकृति सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से भार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पीतलदान पर प्रलग-प्रलग भुगतानों को व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आवार पर अवधि पीतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान को व्यवस्था होनी चाहिए। विवेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किसी की अर्ण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए:—

“साथ पत्र की प्रति के बाद..... महीने परन्तु अधिक से अधिक..... के अल्ल तक पूर्ण किया जाना है। पीतलदान के लिए आविरी सियि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि ३१-१२-१९८५ के बाद की न हो।”

लाइसेंस २. संभरण ठेके का समझौता करने समय व्यापार में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की नियम के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होता चाहिए जो कि भारतीय रूपए में चुकाना चाहिए।

भारतीय रूपए या किसी भी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिवर्तन में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रप आवेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेश केवल अप्रेजो में होना चाहिए।

2(2) शी०सी०पी०एफ० येन क्रिटिक (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत नियंत्रण अनुबन्ध-२ में दिए गए हैं। लेकिन, यदि माल और सेवाओं के लिए शी०प्र०जारीक लुली अन्तर्राष्ट्रीय निविश से दिए अधिप्राप्ति क्रियाविधि अनुमति का विचार है जिसका भुगतान अर्ण को प्रति यदि से किया जाएगा तो इसका पूर्ण अनुमोदन नियम से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि (यों) अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र विधिवत् प्रधिकृत व्याक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और कारणों सहित नियम को भेजे जाएं।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पहले बोलियां के लिए सभी नोटिस, आवेशों, बोलो प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टकरण और इलाइट और बोलो लगाने से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां पूर्व अनुमोदन के लिए नियम को भेजी जाएंगी। शी०सी०पी०एफ० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त वस्तावेज

5 (2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबन्ध-3 (भास्त्रविक प्रायार्थों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवार्थों के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के भास में अपपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी प्राप्तिक सहकारिता निधि (ओरोईंगोरोएफ०) भारतीय दूतावास टोकियो भारत में भायारक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी संजोगा।

सी०१०८०० एण्ड प०० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साक्षरता घोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविवा संशोधन या अन्यथा के लिए प्रावश्यक समझे जाने वाले ऐसे तभी प्राधिकारपत्र/मानव पत्रों के संशोधनों पर स्वतः सामग्री होती ।

5(3) माल का पोतलावान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से भावपत्र में उल्लिखित वस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि वस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाब आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी व्यायिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साम्यपक्ष को खोलने रख-रखाव और परिवालन पर किए गए सभी खर्च विवेशी संभरकों के लेखे में जाएंगे। इन: भारतीय बैंक टोकियो संभरक बैंक से सभी खर्च प्राप्त करेगा वस्तावेजों को संभाल के रखने और मौल-तोल करने और ग्रन्थ आकस्मिक खर्च भी संभरकों द्वारा किए जाएंगे।

संभरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त तिथिशालूक माल की सागत के भुगतान की तिथि और प्री०इ००५०० द्वारा प्रतिपूर्ति की सिधि के बीच के समय का व्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ २५-३-८० को हुए समझौते की शर्तों के भनुतार माप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास जापान द्वारा व्याज भुगतान पर किया गया अर्च भाक एवं तार विभाग [दिव्यें अण्ड अ-८(४)] से प्राप्त किया जाएगा।

पार्वत 6. एप्पा बिक्रीप करने के लिए उत्तरवायित

6 (1) भारतीय ईंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संक्षिप्त अनुसार डी०जी०पी० ए४८ टी० के प्राधिकृत ईंकर को परकार्य जहाजरानी वस्तावेज भेजेगा और ईंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी वस्तावेज रिखा हाने से पहले भारतीय रिजर्व ईंक नई विल्सी या भारतीय स्टेट ईंक तीस हजारी विल्सी में रुपया निषेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रूपए सार्वजनिक सूचना सं० ७४ आई०टी०सी०(पी०एन०)/७४, विनांक ३१-५-१९७४ में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किए जाएं। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रूपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० १०९ आई०टी०सी०(पी०एन०)/७४, विनांक ३-८-७४ और सं० ८ आई०टी०सी०(पी०एन०)/७६ विनांक १७-१-१९७६ में निर्धारित क्षरीकों के अनुसार निश्चित की गई है जो मुकुल नियन्त्रक, आयात-नियर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व ईंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिवर्तों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निषेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स ए४८ ए४९०सिज-८४३ सिविल डिपोजिट्स फार परवेजिज एटस्ट्रा एब्रो अन्डर जेडिट्स लोन एसीमेंट" लोन फास दि गमर्नरमेंट भाफ जापान ५.० विलियन येन जेडिट सं० आई०टी०पी०-II फार द्वार संचार परियोजना सं० (३) होना चाहिए।

6(2) उमर उल्लिखित घनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ ईंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साथ में सार्वजनिक सूचना सं० 184 आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233 आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 24-10-68 सं० 132 आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आई०टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए ।

6 (3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय आधिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह प्रतिरिक्ष धनराशि सेवा खातों के निमित्त देंगे जो वित्त मंत्रालय (आधिक कार्य विभाग) द्वारा मार्गी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का मुनिष्य कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132 आई०टी०सी० (पी०एन०)/७१, दिनांक ५-१०-१९७१ के पैरा-२ में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेयण और प्रायिकारी (यदि कोई हो) के पूरी व्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। अजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पर संख्या और दिनांक

(अ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निषेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संर्वे वेते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए बजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष वेते हुए पंजीकृत बाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

हित्प्रयः भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इपए का निषेध भारतीय बैंक, टोकियो सी आयातकी की सुचना और इपरिवर्तनीय पोतलदान वस्तावेजों की प्राप्ति 10 दिनों के भीतर निरपेक्ष रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए००० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई विली को सूचित कर दिया जाएगा।

6 (4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियमय नियंत्रण प्राप्ति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस०" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए। भारतीय गृहावास, टोकियो द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो को व्याज खर्च आविष्कार के सम्बन्ध में येम की समसुल्य रपए में किए गए भुगतान की गणना भी उपर्युक्त खण्ड-6 भी कंडिका 6 (1) में निर्धारित विविध के अनुसार की जाएगी। मुख्य लेखा अधिकारी, विवेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी०ए०ए० ए०४३ ए०० उचित अन्वेषण जारी करते रहेंगे।

पार्ष 7. विविध व्यवस्थाएँ

7(1) आयात साइर्स के उपयोग करने की रिपोर्ट

भ्रायातक का पोतलदाम और उसके भ्रधीन किए गए भ्रगतान और शेष धनराश के बारे में साखपत खोलने के बाद तक मासिक एपोर्ट सहायता लेका एवं लेका परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, विस मंदिरालय, यू०सी०स००० बैंक विलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को मेजरी आहिए।

7(2) संभरकों की विशेष शर्तों के बारे में प्रधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को प्रवर्गित करा देता चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालनी है।

7(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरवाचित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, ट्रीक्यों द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों प्रत्यक्षध 3 में “सुगतान की शर्त” के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएँ शामिल होनी चाहिए।

7(4) प्रतिष्ठा प्रनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० प्राई०पी०डी०पी०-II के प्रधीन सभी आधारों को विवेदी प्राधिक सहयोग निर्धारित, जापान (प्राई०सी०एक०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियोगों, अनुबंधों या धारेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(5) प्रतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियंत्रण (नियंत्रण) प्रधिनियम के प्रधीन उचित कार्रवाई की आएगी।

7(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध-1	पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध-2	प्रधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन
3. अनुबंध-3	प्रधिकार पक्ष जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध-4	प्राधिकार पक्ष का प्रपत्र
5. अनुबंध-5	साख पक्ष का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए सारू)
6. अनुबंध-6	साख पक्ष का प्रपत्र (सेवाओं के लिए सारू)

अनुबंध 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासील देश तथा उनमें क्षेत्र¹
(ख) अ०पी०ई०सी० से मिल विकासील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिल
मोरोको
तुनीशिया

2. अफ्रीका इकिसी सहारा

धारोला
ओस्त्रोना
वरण्डी
कैमेरन
कैप बड़ी द्वीप समूह
केन्या अफ्रीका गणसंघ
चाव
कमोरो द्वीप समूह
कांगो डाहिमें का गणतंत्र
भूमध्य गिनी (1)
इथोपिया

गाम्बिया

भारत
गिनी
आइथरी कोस्ट कैमिया
लेसोथो
नाइबोरिया
भालागासी गणतंत्र
मासाई
माली
मारिसेनिया मारीशस
मुजाम्बोक
नाइगर
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेनिया
खान्दा

सेंट हेरेसना और हेम (2)

स.ओटोप और प्रिसिपल
सेनेगाल
सिचलीज
सियरा लियोन
सोमालिया
सूडान
स्वाजी लेप्प
टेरी आयर्स और इसास (3)
टोगो
युगान्डा
तजानिया संयुक्त गणतंत्र
अपर बोल्टा
जाइरो गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केंद्रीय

बहमास
बारबाडोस
बेलिज
बेरमुड
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकान गणतंत्र
एस साल्वादोर
ग्वाटे लोप
ग्वाटे माला
हेती
होण्ड्रस
जेमेका
मार्टिनिका
मेक्सिको
नीदरलैण्ड एमटिलीज
निकारगुआ
पनामा
सेंट पियरों और मिक्योलोग
ट्रिनिडाड और टोबॉगो
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एन०प्राई०ई०
(क) संबंधित राज्य (4)
(ख) आन्ध्रित (5)

4. बहिणी अमेरिका

आर्जेन्टीना
बोलिविया

प्राचीन
चित्री
कोलम्बिया
फालकैण्ड द्वीप समूह
फासीसी गिनी
गुयाना
पाराम्बे
पीर
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मुख्य पूर्वी एशिया

बहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिप्राई अरब गणराज्य
यूनाइटेड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणराज्य
यमन जनवादी अमार० (4)

(1) पहले सेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डोपी द्वीप सहित।
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित:—
भ्रसेन्न, द्रिस्टन डा इन एक्सोसेविल्स, नाइटिगेल गाफ
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब, बोनेरे क्युराकामो जाहा, सेंट यूस्टाफिट
बेन्ट मार्टिन (विकिणी भाग)।

6. दक्षिणी एशिया

अफ्नानिस्तान
आगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालदीप
नेपाल
पाकिस्तान
भी संका

7. दक्षिण पूर्वी एशिया

बर्नी
हांगकांग
बन्दर गणराज्य
कोरिया गणराज्य
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणराज्य
वियतनाम जनवादी गणराज्य

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिर्लंड घीर इलाइस द्वीप

प्रासिसी पोलिनेशिया (5)
नीह
स्पूक्सेस्कोनिया
न्यू हैपिसिल टेसिसेस (आ० और के०)
निय
पेसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (आ०)
टोंगा
वालिस और फुनुना
पश्चिमी समाधो

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राइलर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप समूह पांटगुवा, डोमिनिका, प्रेनाडा, सेंट किट्स (सेंटकोरिस्टोफे) नेविस-एंथेला, सेंट लुसिया और सेंट विंसेंट।
(2) मुख्य द्वीप समूह, भोलोसेरात, जेमान, तुर्कस और कार्डिकोस और ब्रिटिश डर्जिन द्वीप समूह।
(3) अजमान, बुर्भी, फुजाइरह, रास अल जेमान, शारजाह और उम अल क्वेबेन।
(4) अब्दन और विजेय सुलतनत और अमीरात सहित।
(5) सोसायटी द्वाप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए अस्ट्रेल द्वीप समूह दुमामोदु जम्बीजर प्रूप और मार्केस द्वीप समूह।
(6) पेसिफिक द्वीप समूह का द्रस्ट प्रवेश, कोरीलीन द्वीप समूह, मार्शी द्वीप समूह और बेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)।

(क-2) ओ००१०१०१० के स्वरूप या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लिबियन अरब गणराज्य
गेब्रान
नाइजीरिया
इमेरेटर
बेल्जियम
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
अबुधाबी
एप्पोनेशिया

अनुच्छेद-2

ओ०१०१०१०१० दृष्टारा व्यवस्थित एरियोजना अर्जन के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग-वर्णन

1. विजापूर

प्रीप्राचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निकिया के अधीन सभी संविवाएं बोली मार्गनिक करने के लिए जहाजी देश में सामान्य प्रवार के लिए कम से कम

एक समाचार पत्र से विश्वासित होना चाहिए। विश्वासन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्नोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2.1 बोली वाप्त या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इन्होंने अमाना चाहिए जिसमें कि उचित बोली कार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली शाष्ट्र भ्रष्टवा गारंटियां शमकत बोलीकारों को रिहा कर देना चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रश्नामन और उसके अधीन किए गए किसी परिवर्तनों में की गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियन्त्रण किया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार समर्ट रूप से परिभ्रामित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन नियेशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्थलप और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मर्दों के या एक मूल कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए वेनों के सम्बन्ध के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में कुछ गई संविदा की किस्म की स्पष्ट आलोचा होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रति पूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नियम को स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्मकी संविदाएं) यदि अपेक्षित वेश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

ये नियांतक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तवान अर्हण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके आद "पात्र संभरक" कहा गया है) पात्र स्नोत देशों से राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:—

- (1) अभिनाव किए गए गेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्नोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक नियेशनों का बहुमत पात्र स्नोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) तेसे न्यायिक "द्यक्षिणों" का पंजीकरण पात्र स्नोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए शर्तों कि संविदा कीमत का वह भाग ठेकेदार अर्हण के देश में अब फरेगा अर्हण की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समीक्षन अधिकार

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्षों कीमतों में बढ़ि भी आवश्यकता है भ्रष्टवा बोली की कीमतों में बढ़ि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवधियों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूख बोली दस्तावेजों में साफ-माफ परिभ्रामित होना चाहिए। माल की सप्लाई के लिए संविदायों में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदायों में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्वर सुपुर्व किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग नियेशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिवर्त्य का आभास नहीं करती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजन किया जा सके।

(ग) बोली

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताशरित संविदा या विवेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्पित क्षय आदेश यो भारतीय आयातक द्वारा विवेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियों भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पाक्षता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा:—

"मैं (हम एवं द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र संभरक है ज्योंकि शेयरों का प्रतिशत (%) (पात्र स्नोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है और प्रतिशत () नियेशन (पात्र स्नोत देश) के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी) कंपनी (पात्र स्नोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मानदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह वर्णन यो जाना चाहिए कि आपन शोधोनिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार लिए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पर्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोडिके बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 बाष्टीभालों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतु पुर्जों की आवश्यकता है या यह नियन्त्रण किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं के बानाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिप्ली की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल बाष्टी भाल, सूची, संब्या और विशेष विनियमिता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पर्यवस्तुओं के प्रस्तावों की प्रमुखता देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारम्टी, निष्पादन बोर्ड और रोको एवं गर्जन प्रवराणि

मानकिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारम्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए सब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो वैक गारम्टी द्वारा भ्रष्टवा निष्पादन बोर्ड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और प्रवराणि के मानकीरण भ्रष्टवा भ्रष्टवा में कमो पाए जाने के मामले में अर्हण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती घबराई को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने

के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की बनराशि की बोली को वस्तावेजों में निरुपित किया जाना चाहिए।

माल की सम्पादी के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह बांछनीय होता कि वेंक गारंटी अथवा बांड की अवेक्षा गारंटी निष्पावन के लिए रोक रखी गई बनराशि के हो कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर माना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि वेंक गारंटी अथवा बांछ जुना जाता है तो वह केवल नाम माल धनराशि के लिए ही हीना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली अति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या मुपुर्दी में देर होने के कारण फालतू खर्च, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली वस्तावेजों में चुकाई जाने वाली अति से संबद्ध आवधान शामिल होने चाहिए। टेकेदार द्वारा संविदा में निर्विष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय पर पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो, तो टेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में आमिल की जाती में अब उचित हो तो इसे अनुबंधित करने हुए इस संबंध में बाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने वायिदों को न पूरा करना उत्तराधार में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवरण विधियों में (फोर्स जेवोर) के कलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिमाण भी जानी है)।

7. ज्ञानों का विपराम

हागड़ों के विपराम से संबंधित व्यवस्थाएँ संविदा की शर्तों में शामिल भी जानी चाहिए। यह बांछनीय है कि व्यवस्थाएँ प्राकर्तृत्वीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए “समझौते और व्यवस्था निर्णय के नियमों” पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएँ जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित हीना चाहिए।

8. आपात की व्यवस्था

बोली दस्तावेज अंगेजों में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य आपा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंगेजों भी होली चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी आपा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और डेका देना

9. 1. बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः प्रकर्तृत्वीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जाती चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलोंकारों को अपनी बोलियों प्रस्तुत करने से पहले स्वान पर भली आंति देखभाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हीना चाहिए।

9. 2 बोली खोलने की विधाविधि

बोलियों की अन्तिम पार्टी के लिए और बोली लगाने के लिए अतिथि समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए।

और सभी बोलियों निर्धारित समय पर खुने आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे रहे हैं तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9. 3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, आपाकार किसी भी बोलीं खोलने वाले से प्राप्ती बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9. 4 गुल रडो जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित मिकारियों के बारे में भी उस अविकृत को जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9. 5 बोलियों की जांच

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित है और क्या बोलियों सामान्यता अवधार रूप से मही है, यदि बोलियों मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उनमें प्रत्येक भाग मही हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार मही हैं तो उन्हें प्रत्येक भाग किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9. 6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएँ

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस आत का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से बदलने के लिए अनुमति दी गई और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9. 7 बोलियों का सूच्यांकन और मिलान

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं जाती के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए संमजित बोली की कीमत के अनुसार व्यापक रूप से विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी जाए। जाती कीमत के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-कुशलता एवं संगतता या कार्य-कुशलता की उपत्यकाएँ और प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रदीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकरण के अनुसार एवं ऐसी भागों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समजित कीमत के लिए वृद्धि की बनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य प्राप्त कराया जाता है बोली स्वीकृत होने पर अन्य द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की

नुसना कर्णी द्वारा जूनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली शब्दायेंजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकित में उपयोग के लिए विनियम की वर सरकारी स्वोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर हीर्णी आहिए और जब नक्त नियंत्रण स्वेच्छा में पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब उक्त शब्दायेंजों खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर पात्र होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के नियंत्रण को अधिसूचित करने समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली वस्तावेजों में सकान्यना यह व्यवस्था की गई है कि कर्णी सभी शब्दायेंजों को अस्वीकृत कर नक्त करें हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोगजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियों आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनरक्षण द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों और अस्वीकार करने के लिए तब औपचारिक देशों आहिए जहाँ (क) बोलियों, बोली वस्तावेज के आशय के अनुमार नहीं हैं या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों और अस्वीकार कर दिया जाता है तो कर्णी को चाहिए कि वह उम कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे। जिससे प्रब्लीकृत मिल की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परियोधन पर। (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पन्थ वस्तुओं की धनरक्षण पर) या दोनों पहले विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निष्ठा पर विचार करने के बाव अर्णी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली खेत्र वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर भक्ता है।

9.9 संविदा का नियंत्रण

संविदा का नियंत्रण उम बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो धमना और विस्तीर्ण साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह नियंत्रण को एक एते के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित अन्य वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परियोगित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

ग्रन्तबन्ध-3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना चल

सं० दि०

सेवा में,

महायना लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय

आधिकारिक कार्य विभाग,

मू० सी० औ० बैंक बिल्डिंग, प्रयम मंजिल,

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001

विषय :— येन ब्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से का आयात।

महोदय ,

उपर उल्लिखित येन ब्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन से जो कि के आयात के संबंध में (बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ह) में सम्बद्ध सम्बन्धित करने के लिए

1359 GI/81-2

दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्न-लिखित और ग्रम्यता करते हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, रिनांक और मूल्य , वह तारीख जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के नामके क्या वह सीधे क्या या औपचारिक रूपे अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आवारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण महिने यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्वाचित अन्यकुल न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आद्यार पर किया गया है।
- (घ) माल का संभित्ति विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) यदि कोई हो तो पात्र से द्वारा स्त्रोत देशों में आयातित संघटकों का प्रतिशत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निष्पक्ष मूल्य (येन में)
- (ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनरक्षित (येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निष्पक्ष मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।
- (झ) सम्बन्धित के संभरकों के साथ यह गई संविदा को गोप्या एवं दिनांक
- (ट) सम्बन्धित के संभरक का नाम और पता :—
 - (१) राष्ट्रिकता
 - (२) पात्र स्त्रोत देशों के गण्डियों द्वारा लिए गए शेयरों का प्रतिशत
 - (३) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवाम स्थान
 - (४) उन निवेशकों का प्रतिशत जो मात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।
- (झ) ये भुगतान शर्तें और संभावित नियंत्रित जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगी।
- (झ) सुपुर्की को पूर्ण करने की प्रत्यापित तिथि
- (झ) भारतीय बैंक टोकियों को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान विवारण हुए)
- (झ) पोलिदान अन्देश वाहनान्तरण/पार्टिशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए।
- (झ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (झ) क्या उगां लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं, और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हाँ तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, वित्त मंजिल और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत औ०१० सी० एफ० को हमें अधिसूचित किया गया है।

अनुच्छेद-4
(प्राधिकार-पत्र का प्राप्ति)
संख्या एफ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—येन केहिट (परियोजना महायता) अट्टण करार सं०.....
के प्रधीन आयान साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र
जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की पार्टी के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न और के अनुसार संबंधी.....
.....के नाम में.....
ऐन धनराशि के लिए प्रपरियोजनीय साख-पत्र खोलने के लिए प्राप्तिकृति किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साख-पत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०८०८०८०८० भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पूर्णकृति की जाए।

साख-पत्र की पार्टी के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओ०८०८०८०८० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ०८०८०८०८० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के बीच के मध्य के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही व्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खाते जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए अच्छे भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परकारात्मक दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के खातों के खजे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ें और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०८०८०८०८० में नहीं किया जा सकता।

यह प्राधिकार-पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मध्य खोले गए आये के नए साख-पत्र या साख-पत्र में आद के संघोषणों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार-पत्र तक बैंक अपेक्षा रहेगा।

सचिवीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक के बैंक 1 उसमें निम्नेन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से वस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन के बशावर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बशावर रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई०टी०सी० (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई विल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, विल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका व्यान सार्वजनिक सूचना संख्या-184 आई०टी०सी० (पी एन)/68, विल्ली 30-8-68, संख्या-233 आई०टी०सी० (पी एन)/68, विल्ली 24-10-68, संख्या-132 आई०टी०सी० (पी एन)/71, विल्ली 5-10-71, संख्या-74 आई०टी०सी० (पी एन)/74, विल्ली 31-5-74 और संख्या-103 आई०टी०सी० (पी एन)/78, विल्ली 12-10-1976 की शर्तों की ओर विलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह “के डिपोजिट्स पाण्ड प्रॉविन्स 843 मिलिन डिपोजिट/डिपोजिट्स फार परचेसित्र एट्सेक्ट्रा एक्राट परजेजिस अन्डर क्रेडिट प्रोमेंट 1979-80 के लिए 5 विलियन येन केहिट (परियोजना महायता) सं० आई ही पी-II फॉम दि गवनरेंट आफ जापान से अहण” है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई विल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई०टी०सी० (पी एन)/71, विल्ली 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके बालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रयोग पत्र भास्ति उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रण,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, पू०सी०धो० बैंक बिल्डिंग,
संमव मार्ग, नई विल्ली-110001

जिन मामले में तुल्य रुपया उपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी दृष्टि द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रूपए का पूरा अंश इस विभाग को भेजना चाहिए।

यदि कोई हो तो, बैंक के खाते, द्वारा और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खाते (जिसमें विदेशी संभरकों के खातों के खजे भी शामिल हैं) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय, नई विल्ली को समतुल्य रूपए अदा करने पर ही तब किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा उचित सलाह बैंक आफ इंडिया, टोकियो भारतीय दूतावास जापान में सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी।

3. निदेशक, अट्टण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सम्योग निधि, टेकबसी म्यूडी बिल्डिंग, 4-1, श्रीहाटमैयची-1-कोमे, चियोडा-कू, टोकियो-जापान।
4. भारतीय दूतावास टोकियो।
5. अवधर मंत्रिव. जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई विल्ली।

लेखा अधिकारी

दिनांक के बीच समझौता सं०
दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के
अनुसार समुदायार आर्थिक महायता निधि द्वारा
..... की धनराशि (.....
..... येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक
निष्पादन विवरण जारी करता है ।

(.....)
(ऋणी)

द्वारा
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुबोधः—

दास्ताविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्णिया जाएगा ।

ऋण अन्ध-६
(प्रपत्र अ००९०सी०एफ०एल०सी. -२)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र
(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक
सेवा में,

यह साख-पत्र ऋणी और विवेशी
आर्थिक महायोग निधि के बीच हुए ऋण
करार सं०
दिनांक के अनुसरण
(संभरक का नाम व पता) में जारी किया गया है ।

प्रिय भ्रातृय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूरी व्यापर मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम वा रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं०
खोल दिया है जो येन
(येन पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा
..... और परियोजना) से
संबंधित दस्तावेजों को नम्यी करना है सीधा तय करने के लिए ड्राफ्ट
..... से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साखपत्र सं०
दिनांक के अन्तर्गत भूता लिए गए हैं, से विनिहित
होने चाहिए ।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

हम एतद्वारा बताने हैं कि इन क्रेडिट के अन्तर्गत हमकी शर्तों
का अनुपालन करके भुताए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आवेद-
शितों को दस्तावेजों की सुपुदंगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारार्थक बताया जाए यह क्रेडिट "यनि-
फार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाक्सेन्टरी केहिडस (1974 रिवीजन)
इन्डरनेशनल बैंकर एंड फारम्स, नं० 290" के अधीन है ।

सौंदर्य करते वासे बैंक को विशेष अनुबोधः—

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के
पावात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्भागित

भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतान के
मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बाजाएँ लाभकारी विवरण की
आवश्यकता है ।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए बचत बहुता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक महायोग निधि से
अपने भुगतानों के सिए प्रतिपूर्ण प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धन-
राशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के
अनुसार प्रेपित करने का बचत देते हैं ।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और
मसीदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजें जाएंगे ।

4. हम साथ के अन्तर्गत बैंक के सभी छाँचें संभरकों के लेखे के लिए
हैं ।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं०
का एक अभिन्न भाग है ।

प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि येन

कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है
अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अनिम्न भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण व्योग की धनराशि येन
कुल संविदा मूल का प्रतिशत
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है:—

वेन धनराशि

अन्तिम भुगतान राशि

येन
पहली किस्त येन
दूसरी किस्त येन
.....

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी
किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र
संलग्न है ।

निष्पादन का विवरण

दिनांक
संवर्धे

सेवा में,

.....
.....
.....

(संभरक का नाम और पता)

संवर्धे:—ऋण करार सं० के
प्रत्यर्गत परियोजना से संबंधित
के नाम में येन के लिए
..... द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं०
दिनांक । मैं, अधिकारी, प्रतिनिधि

(अण) एतद्वाग और
 के बीच समझौता सं०
 दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के
 अनुमान अमुक्ताग्र आर्थिक सहायता निधि द्वारा
 की धनराशि (..... येन केवल)
 प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता है ।

(.....)
 (अणी)

द्वारा
 (प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विषेष अनुदेश:—

धार्मिक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्णिया जाएगा

परिचय-2

धार्मिक विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 10

आई टी सी (पी एन)/४२, दिनांक २४ फरवरी, १९८२ का परिचय

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किए गए दूरसंचार परियोजना (४) के लिए येन ९.४ बिलियन के येन क्रेडिट के प्रधीन माल और सेवाओं के प्रायात के संबन्ध में लाइसेंस गर्ते ।

खण्ड 1. सामान्य शर्त

(१) इक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना की प्रायात आवश्यकताओं को वित्तान करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किया ९.४ बिलियन येन का ऋण विकासणील देशों के लिए खुला है । नदनुमान, इस क्रेडिट के प्रधीन अधिकारात की जाने वाली बस्तुएँ और सेवाएँ जापान और अनुबन्ध-१ की सूची में उद्धृत सभी देशों से प्रायात की जा सकती हैं । मैं देश इस कठन के अन्तर्गत पाव ज्ञान देश होंगे ।

(२) क्रेडिट के प्रधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास पौजीगत माल समिन द्वारा विषेष रूप से तिकासी कर दी गई है । इस क्रेडिट के प्रधीन जारी किए गए प्रायात लाइसेंस (सं०) का मूल्य येन १०,५०० मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (१) में कहा गया है ।

प्रायात लाइसेंस का रूप में मूल्य, गजस्व विभाग (सीमा गुल्क) द्वारा अधिकृत विनियम द्वारा और प्रायात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रतिनिधि वर और मूल्य नियंत्रक, प्रायात-नियंत्रित द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं०-७८ आई टी सी (पी एन)/७४, दिनांक ६ जून, १९७४ के पैरा २ के अनुमान प्रायात लाइसेंस में संकेतित वर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा गुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी प्रायात लाइसेंस (सं०) में विनिर्दिष्ट मूल्य विनियम वर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे । लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई टी पी-१२" होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोड होगा । डी०जी०पी० एण्ड टी को प्रायात लाइसेंस भेजने समय मूल्य नियंत्रक, प्रायात-नियंत्रित के पत्र में भी हसे द्वुराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठाकृत की जानी चाहिए ।

(३) लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल डी०जी०पी० एण्ड टी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

(४) डी०जी०पी० एण्ड टी० की सुविधा पर निर्भर करने हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन, कुल मूल्य येन १०,५०० मिलियन (लागत बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (१) में कहा गया है ।

(५) प्रायात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि डी०जी०पी० एण्ड टी० द्वारा आवेदन करने पर ३१-१२-१९८५ तक दी जा सकती है । इसमें प्राप्त की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) की भेजा जाना चाहिए ।

(६) क्रेडिट के प्रधीन विचारन किए जाने वाले प्रायात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् संत्वापित संत्वान माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है ।

(७) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेपण की अनुमति प्रायात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अधिकारी के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय प्रभिकर्ता को भारतीय रूपए में किया जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होने और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

(८) पक्के अनुबन्ध-१ में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर्यात विशेषक के आधार पर दिए जाने चाहिए और ये प्रायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से ४ महीने की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रूपए में भारत में देय होगा । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रम प्रादेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय प्रायातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रम संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के प्राविदेश या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण प्राविदेश स्वीकार्य नहीं है ।

(९) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू०-८० । अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा (१) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर बैंक कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करने हुये लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आविदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पत्राना के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की ओर अवधि के लिए वृद्धि प्रश्न कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से ४ महीनों से अधिक के लिए सार्वी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मासमें को पत्राना के आधार पर विचार करेंगे और प्रत्येक निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रवान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, प्रायात लाइसेंस के प्रधीन किए गए संदरण ठेकों में वैक गारंटी साथ पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रूपया जमा कराने प्रादि की स्वीकृति सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

(१०) प्रायात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पोनतान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पांत-

मन्दान वस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक में भारतीय आयातक को किसी भी किस की छूट सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के विवरण की अधिकता के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

“साथ पत्र की प्राप्ति के बाद……महीने परन्तु अधिक से अधिक……के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।”

पोतलवान के लिए आविरी निधि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यद् निधि 31-12-1985 के बाद की न हो।

खण्ड-2. सम्भरण ठेके का समझौता करते समय आयात में रखी जानी वाली विशेष बात

2 (1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अधिक्यकृत होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकृती का कसी-शन यदि यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपए में जुकाना चाहिए।

भारतीय रूपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिमिति में अधिक्यकृत नहीं होना चाहिए। अत्र आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश के बल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2 (2) आरो ५० सी० एक० येन ट्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाओं की अधिकारिति के लिए विस्तृत निःशुल्क अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं। माधारणतः माल और सेवाओं की अधिकारिति और प्राचारिक खुली अन्तर्गतीय नियिदा के माध्यम से की जानी चाहिए। लेकिन, यदि माल और सेवाओं के लिए और प्राचारिक खुली अन्तर्गतीय नियिदा से भिन्न अधिकारिति क्रियाविधि अपनाने का विचार है, जिसका भुगतान छूट की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिकारिति क्रियाविधि (मों) अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र विधिवत प्राधिकृत अधिकृत द्वारा हस्ताक्षित और कारणों सहित आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) के माध्यम से निधि को भेजे जाएं।

माल और सेवाओं की अधिकारिति के लिए बोनिया असमिति करने से पहले बोनियार्कों के लिए सभी नोटिस, आवेदनों, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविवा, विशिष्टिकरण और ड्रॉइग्स और बोली लगाने से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतिनियों पूर्व अनुमोदन के लिए अधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) के माध्यम से निधि को भेजी जाएगी। (आरो ५० सी० एक० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज़/आवेदन) पत्र दो प्रतिनियों में आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाएं।

2 (3) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, देंकियों द्वारा 1980-81 के लिए आरो ५० सी० एक० येन ट्रेडिट (परियोजना सहायता) म० आर्ड० डी० पी०-12 के अधीन योने गए अपरिवर्तनीय आवधन के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसका व्योग नीचे खण्ड-6 में दिया गया है।

2 (4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही गंविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुल विशेष मामलों में, एक से अधिक संविवा करने की अनुमति भी दी जा सकती है। जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की निधि के नुस्खे बाद वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर देना चाहिए।

2 (5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्तोत्र देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्तोत्र देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्तोत्र देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शामिल होंगे।

2 (6) संविवा में घोषणा

प्रध्येक संविवा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

मैं, अधीक्षिताकारी प्रदूषद्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभारित किया जाने वाला माल……में (पात्र स्तोत्र देश) उत्पादित है।

मैं, अधीक्षिताकारी प्राप्त यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विवाद के अनुसार अपाद्र लोन देशों से आयातित भाग निम्नलिखित रात के अनुसार 30% से कम है।

आयातित लागत बोमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य $\times 100$

और

मैं, अधीक्षिताकारी एन्ड्रू प्राप्त सत्यापित करता हूं कि……(पात्र स्तोत्र देश का नाम)

मैं……(कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्तोत्र देश के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है।

2 (7) अपाद्र लोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में आपाद्र स्तोत्र देशों में बड़ी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तवान किया जा सकता है बगते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

आयातित लागत—बोमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क

$\times 100$

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

खण्ड-3. सम्भरण ठेकों में समाविष्ट भी जाने वाली शर्तें

3 (1) सम्भरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष स्पृ से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की अवधार भारत सरकार और जापान की विदेशी आधिक सहयोग निधि (आरो ५० सी० एक०) के बीच द्वारा संचार परियोजना (4) के लिए येन ट्रेडिट म० आरो ५० सी० पी०-12 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए अप समझौते के अनुसार होनी चाहिए और वह भारत सरकार और विदेशी आधिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आधिक सहयोग निधि (आरो ५० सी० एक०) के बीच येन ट्रेडिट म० आर्ड० डी०-पी० 12 से सम्बन्धित 15 अक्टूबर, 1981 को हुए अप समझौते के अन्तर्गत बैंक आैफ इंडिया ट्रांकियों द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साल्प्रत के गाध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक पेनी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगा जो एक और भारत सरकार द्वारा आरो दूसरी और आरो ५० सी० एक० द्वारा येन अप के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) 2 (6) में उल्लिखित प्रपत्र प्रमाण पत्र तीन प्रतिनियों में

3 (2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण मंत्रिता के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, ट्रांकियों के परामर्श पर पोत एक्टिव्हून अवधार करने के लिए गहमत है और इस उद्देश के लिए वश भारतीय दूतावास, ट्रांकियों को, शामिल माल की सुरुर्की के यार्डेक्रम से अवधार कराया जाए और पोतनदान कम से कम 6 मासाह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिसमें कि उल्लिखित आवश्यक हो सके। विदेशी मामलों में, जहाज भारतीय आयातक इन्ड्रुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किए जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतनदान के परामर्श आवधार और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास ट्रांकियों को भेजी जानी चाहिए।

बाण्य-4. विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा ठेके का प्राप्ति सोबत

4(1) लाइसेंसधारी को पक्ष का प्रादेश देने के लिए, तिथिरित प्रवश्य के भीतर दो० प्रा० प०० एण्ड टो० घोर लिदेणः संभरको दोनों द्वारा विधियत हस्ताक्षरित थेके को चार प्रतिया जो विदेषी संभरको द्वारा लिप्तित में पृष्ठि अविषेक के साथ हो या उनको घोर प्रकार में पूरी फोटो प्रतियां भेजन विध ग्रायात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां सहित, जापान अन्तर्भाग, प्रायिकत कार्य विभाग जित मंदालय, नार्थ इनाक, नई विल्ली की ओरेजनी आहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि नभी ठेकों के लिए और ठेकों की विधय वस्तु के लिए अनिवार्य अणीप्रथानों के कारण बंशोवर्धनों पर उत्तरकी कीमतों पर भी लाग होगी।

4(3) किंतु भवान्यथ (प्रार्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभव, दूर मंचार परियोजना(3) के लिए ये न केंद्रित में ० भारी ३० डो. पे०-॥ (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तानन करने के लिए विदेशी प्रार्थिक सहकारिता निधि (अं० ००० ३०० सौ० एक०) को संविदा दस्ताविजों की प्रक्रिया उन्नें अनमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

पर्याप्त विवेशी संभरको बो समग्रतात् सामाजिक क्रियाविधि

5(1) विवेशी आर्थिक महकारिता निधि (प्र० ५० मी० एक०) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा दी० जी० पी० एंड टी० और भारतवासी लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद दी० जी० पी० एंड टी० को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद मी० ए०८० एंड ए० कहा जाया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, प० मी० ए०१० बैंक बिलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-३ के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुबन्ध-५ करना चाहिए। मी० ए०८० एंड ए० संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-४ में एक प्राधिकार पत्र जारी करेंगे। जो सम्बद्ध विवेशी संभरक के नाम में (वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबन्ध-५) के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबन्ध-६ के रूप में अवलिकृतनीय सात्यपत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियो (विदेशी आर्थिक महकारिता निधि अर०५० मी० एक०), भारतीय बैंकालम, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय को भी पट्टाकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार पद मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो इन्वेस्टमेंट्स (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में प्रश्नितंत्रीय सापेक्ष की स्थापना करेंगा और उसको एक प्रति विदेशी आर्थिक महाकारिता निधि (आंदो ५० सौ १० लाख) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातके बैंक और मदायाता लेखा (एवं लेखा परीक्षा नियोजन को सभी संजोते)।

सभी ० प्र० प्र० प्र० प्र० से प्राधिकार पत्र के भावधार पर साथेवत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि मंचिदा मंशोधन या अन्वया के लिए प्रावधक्य समझे जाने वाले तिसे सभी प्राधिकार पत्र/साथेवत्रों के मंशोधनों पर स्वतंत्र लाग होगी।

5(3) माल का प्रीतलबान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैकरों के माध्यम से मालावत में उल्लिखित वस्तावेज भूगतान के लिए बैक आए हैंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेंगा। यदि वस्तावेज भूगतान को लिए गए तो बैक आए हैंडिया, टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक का उत्तरके बैकरों के माध्यम से रिहा करेंगा और उत्तरके बाद धनराशि की लागत की धनराशि को प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5 (4) साख-पत्र को खोने, रख-रखाव और परिचालन पर किए गए सभी स्वर्ण विदेशी संभरकों के लिये में जारी हैं। अतः भारतीय बैंक, दोकियों संभरक बैंक से सभी यर्जन प्राप्त करेगा, वस्ताविजों को समझाके रखने और पोल-दोल करने पर अन्य आक्रमिक व्यापारों भी संभरकों द्वारा किया जाएगा।

संग्रहकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जापान पर्यन्त निःशुल्क साल की सालान के भूगतान की निधि और और ३०० हॉ सॉ ०५० द्वारा प्रतिपूर्ति की निधि के ओर के समय का व्यापार भारतीय बैंक उनके और भारत मरकार (वित्त मंत्रालय) के माध्य २५-३-८०) को दुग्ध मस्तौते की गती के अनुभाव प्राप्त करेगा और इनकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास, जापान द्वारा व्याज भूगतान पर किया गया खर्च डाक एवं तार विभाग [द्वेष्व व्यष्ट-६ (४)] से प्राप्त किया जाएगा।

प्र० ६. रुपया निश्चेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6 (1) भारतीय बैंक, ट्रांकिंग मशहूर प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में मंकेनिन अनुग्रह डी० ज्न० पी० एंड टी० के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी इस्ताबेज भेदेरों और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज गिरा है तो ऐसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नहीं दिल्ली या भारतीय स्ट्रेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निकेप कर दिया गया है। विदेशी मंभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए सार्वजनिक सूचना सं० ७-२ आई० टी० सी० (पी० प०००) /७४, दिनांक ३१-५-१९७४ में निर्धारित विधि के अनुसार भारत रक्कार के लेखे में जमा किए जाएं। विदेशी मंभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अतारी जाने वाली विनियम की वर भुगतान को तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० १०९ आई० टी० सी० (पी० प०००) /७४, विनांक ३-८-७४ द्वारा सं० ८ आई० टी० सी० (पी० प०००) /७६, दिनांक १७-१-७६ में निर्धारित नरके के अनुसार नियन्त्रण की गई हो जो मध्य नियन्त्रक, आयत-मियान की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियन्त्रण परिवर्तनों के माध्यम से मरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखे और उपर्युक्त राया निकेप किया जाएगा वह 'के डिपोजिट्स एंड एडवान्स-४-४३ लिकिन डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परवर्तित एंटरट्स एंड अन्डर क्रेडिट्स लीन एंग्रीवेंट' लोन क्रोम दि गवर्नर्सेंट आरोग जापान १०.१ विलयन येन फ्रेंटि० मं० आई० टी० पी०-१२ कार दूरसंचार परियोजना सं० ४ होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या सो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में पा स्टेट बैंक आंक हाईडिया, तीम हआरी रिल्फी में सरकार की मालिय में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दि० 24-10-68, सं० 132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्याचित तरीके में जमा होता चाहिया ।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बावजूद यात्रा रिपोर्ट के भीतर भव्य भारतीय वैकं भी ऊपर निर्धारित तरीके से अहू अनिश्चित धनराशि सेवा खर्च के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए । यात्रान के विशिष्ट कालमों को भरते समय आवायतकों/उत्तरक वैकंगों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई० टी० सी० (पी० एन०) / 21, दिनांक 5-10-71 के वैरा-२ से निर्धारित सूचना चालान के कालम “धन परेवण और प्राविकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण घोषणे” मैं निरखाव रूप मैं निर्दिष्ट किए गए हैं । यजाना चालान मैं निम्नलिखित द्वारे निरपेक्ष रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) विश्व संदर्भात्मक के प्राधिकार पक्ष संज्ञा और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में प्राप्तनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निष्पेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भवत्तान करने की तिथि

उसके पश्चात् सी० ए० ए० ए० ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संक्षेप देते हुए और बैंक तथा पोत परिवहन वस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना बालान रूपी जमा करने का साथ देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० ए० ए० ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह मुनिलय करना चाहिए कि रुपय का निकेप भारतीय बैंक, टोकियो की आवायी की सूचना और प्रधिरवतनीय पोतलदान वस्तावेजों की प्राप्ति 10 दिनों के भीतर नियमदाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तकाल बाद सी० ए० ए० ए० ए० ए० ए० वित्त मंत्रालय (आधिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की गुदा विनियम नियंत्रण प्राप्ति पर इथाना निकेपों की धनराशि का प्राप्तीकरण करना चाहिए और अपेक्षित “एम” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बाप्टिस्ट को भेजना चाहिए। भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो का व्याज और आवाय के सम्बद्ध में येन की समनुवृत्त घण्ट में किए गए भुगतान की गणना भी उपर्युक्त बाप्टिस्ट-6 की कंडिक्शन 6(1) से निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी। मुख्य नेत्रा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के साम में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी० ए० ए० ए० ए० ए० उचित अनुदेश जारी करने रहे हैं :

उपर्युक्त विविध व्यवस्थाएं

7(1) भायत लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और जीवा धनराशि के बारे में साथ पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट दादाता लेना एवं लेना परीक्षा नियमक, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूमी० और बैंक विफिल्ड, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संबरहों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में किए गए कि सी उन विशेष उपदेशों में संभरक को छव्वन करा देना चाहिए जो भाल के लाने में तंभरक पर प्रभाव हापनी है।

7 (3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान में पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध-3 में “भुगतान की शर्त” के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

7 (4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन फ्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० एमी० डी० पी०-१२ के अधीन सभी मार्गभारों को विदेशी आधिक सहयोग निधि, जापान (मी००१००१००१० एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निवेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7 (5) प्रतिक्रिया या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अनिक्रिया या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) प्रधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1	पात्र लोन देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2	प्रधिप्राप्ति के लिए मुद्र्य मार्ग दर्शन
3. अनुबन्ध-3	प्रधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुबोध
4. अनुबन्ध-4	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5	साथ पत्र का प्रपत्र (वास्तविक प्रायातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6	साथ पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध-1

पात्र लोन देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र¹
(क-1) ओ० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश
1. अफ्रीका उत्तरी सहारा
मिस्र
भोरोको
तुनीशिया

2. अफ्रीका विभिन्नी सहारा

अंगोला	कांगो डाहिमे का गणतंत्र
बोत्सवाना	भूमध्य गिनी (१)
वर्गाई	इथोपिया
कैमेरून	नामिबिया
केप बर्डी द्वीप समूह	धाना
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र	गिनी
चाव	प्राइवरी कोस्ट
कमोरो द्वीप समूह	केनिया
कांगो डाहिमे का गणतंत्र	लेसोथो
भूमध्य गिनी (१)	लाइबेरिया
	मालायासी गणतंत्र
	मालावी
	माली
	मारिसेनिया मारीशस
	मुज़ाबिक
	नाइगेर
	तुंगानी गिनी
	रियुनियन
	रोडीशिया
	रवान्वा
	सेन्ट लुइस और लेप (२)
	साओटोमी और ग्रीन्लैंड
	सेनेगाल
	सिच्चलीज
	सियारा लिप्रोन
	सोमालिया
	सुडान

स्वा दी लैण्ड
टेरो आफार्म और हमाम
दोगो
युगाण्डा
तंजानिया संयुक्त गणतंत्र
अपर बोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी ओर कोर्डीय

अहमाम
वारबडीम
बेलोज
बेरमुड
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सल्वेजोर
ग्वाडे लोप
ग्वाटे माला
हेनी
होण्डूरम
जैमैका
मार्टिनिका
मैक्सिको
नीदर लैण्ड एनटिलीज
निकार ग्रा
पनामा
सेस्ट पियरों और मिक्लोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
बेस्ट इण्डीज (शावा) एन०प्राइ० ई०
(क) सम्बन्धित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. ब्रिटिश अमेरिका

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पाराम्बे
पीरू
सुरिनाम
उरुग्वे

5. भृथ पूर्वी एशिया

बहरीन
हजराइस
जार्डीन
लेबनान
ओमन
मिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटेड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी० प्रार० (4)

(1) पहले स्थेनी गिनी का प्रदेश, करनेन्दो पी द्वीप महिब
(2) रामनियित द्वीपों महित :
असेत्तान, विस्टन डा डा एक्सेमिविल्स, नाईटिगेन गाफ
(3) मध्य द्वीप समूह, अरब, बोरेरे क्यूराकाओ, माहा, सेन्ट यूस्टा-
मिस सेन्ट मार्टिन (दक्षिणी भाग)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
वर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. भूत्रू पूर्वी (एशिया)

बहनी
हांगकांग
आमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
मिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. एसिनिया

फोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्ट और इलाइम द्वीप
फासिसी पोलिनेशिया (5)
तीर्क
न्यू कलेंडोनिया
न्यू लेपियिल लेसिसेम (आ० और के०)
नियी
वसिकिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापूवा न्यू गिनी
सोल्मन द्वीप समूह (आ०)
टोंगा
गालिस और कुनुजा
परिषमी ममाओ

9. दूरोप

साइप्रस
जिङ्गाल्टर
चीक
माल्टा
मेन
तर्फ
यूगोस्लाविया

(1) मध्य द्वीप समूह :—एंटिग्वा, डोमिनिका, गेनाडा, सेस्ट किट्टूस
(सेंटकेरिमटीके) नेविस-एनियुता, सेन्ट लुसिया और सेन्ट
विन्सेंट

(2) मुख्य द्वीप समूह :—मोन्सेरान, सेमान, तुर्कस और कोईकोस और डिटिंग वर्जिन द्वीप समूह

(3) ग्रजमान, दुबई, कुजीहराह, रास अल खेमाह, शारजाह और उम अल क्वेन

(4) अबन और विभिन्न सुलतनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करने हुए आस्ट्रेल द्वीप समूह टुमामोदु जाम्बीमर युप और मोकेसम द्वीप समूह।

(6) ऐसिफिक द्वीप समूह का टूस्ट प्रदेश, फोरोलीन द्वीप समूह, भारील द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) घो० फ० १० सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिबिया
लिबियान ग्ररब गणराज्य
गेवान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
बेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
घानादी
हाईडोनेशिया

अनुबन्ध-2

घो० फ० १० एक० द्वारा अवलिप्त परियोजना अ० के अधीन माल और सेवाएं अभिन्नत्व करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन

1. विज्ञापन

ओपनारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए जहाँ देश में सामान्य प्रधार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विशालित होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतिमा पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2.1 बोली के दस्तावेज और संविदाएं

बोली बाप्त या बोली की गारंटिंग साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इसको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोली-कार हस्तोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो बोली बाप्त अधवा गारंटियों असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्राप्तान और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में यी गई संविदा की शर्तों में सायातक और टेकेवार या संभरक के अधिकार और दाकित्य और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभासित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निवेशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं को किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित गाम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मर्दों के या एक मुक्त कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों समन्वय

के आधार पर प्रवान किए जाने वाले माल या सेवाओं के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में जुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट आवश्यकता होनी चाहिए। बास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निष्पत्ति व स्वीकार्य नहीं हैं इंजीनियरिंग उपकरण और निर्याण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रवान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्मीकी संविदाएं) यदि जहाँ देश के लिए तकनीकी और अर्थात् नाम प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे नियर्तिक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान अ० की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बावं “पात्र संभरक” कहा गया है) पात्र स्रोत देशों के शास्त्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे—

(1) अभिवान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रियों द्वारा रखा जाएगा।

(2) पूर्णकालिक निवेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रियों का होगा।

(3) ऐसे न्यायिक “ज्यक्तियों” का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा की कीमत जापान येन में दराई जानी चाहिए बस्तर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो उकेदार अ० के देश में खर्च करेगा अ० की मुद्रा में दराया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन कंडिकार्ट :—बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि प्रक्रीया कीमतों में बुद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में बुद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवश्यकों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) कीमतों के समंजन के लिए विभिन्न सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सज्जाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्राप्त शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्दि किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्राप्त: नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्भान विन्दु उन विभिन्न उपायों के परिवर्त्य का आभास नहीं करती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) शीमा :—सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली शीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संकेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विविवत् हस्ताक्षरित संविदा या विशेष संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्पित श्रय आदेश जो भारतीय आवारण द्वारा विवेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

“मैं, (हम एक० द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संभरक है, स्पैसिक शेयरों का —————— प्रतिशत (०/०) —————— (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिय हैं और मेरी (हमारी) कम्पनी —————— (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।”

4.1 मानवज्ञ

यदि उन गार्डीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टकरण में यह वर्णया जाना चाहिए

कि जापान ग्रोवोरिक भानदण्ड या ग्रन्ति स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड को दूर करने वाली पर्याप्त हो जो मानदण्डों की कोटि में बराबर या इससे अधिक मानदण्ड का सुनिश्चित करती है, उन्हें भी स्वीकार कर दिया जाएगा।

4. 2 बांड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुजों की आवश्यकता है या यह निष्वय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक छिपों की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल प्राण्ड नाम, सूची, संख्या और विशेष विनिर्देशों के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलसी-जुलसी है और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गृह उनमें है।

4. 3 गारन्टी, निष्पादन, बांड और रोकी रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किसी और परिणाम के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में अर्णी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निश्चित किया जाना चाहिए।

माल की समाई के लिए संविदाओं में आमतौर पर यह बांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड जुना जाता है तो यह केवल नाम माल धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली अति

अर्णी को जब कार्य पूर्ण होने या सुनुदी में बेर होने के कारण फालतू बच्चा, राजस्व को हानि या ग्रन्ति लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली अति से समझ प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निमंण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्ण पूर्ण किया गया कार्य अर्णी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोलने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाल्यकारी परिवर्तन

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करने हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उम हालत में एक चूक महीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्जोर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है।)

7. शगड़ों का निपटान

शगड़ों के निपटान से सम्बन्धित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह बांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय आणिज्य

मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और सम्बन्धित मिर्णी के नियमों" पर या ग्रन्ति ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक बोनों को स्वीकार्य हो, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याप्ति

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में ग्रन्ति भाषा इस्तेमाल में जायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9. 1 बोलियों के आमतंत्र और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेंचीदारी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निमंण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियों प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली-भांति देखाना करने के लिए शाम तोर पर कम से कम 90 दिन लिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9. 2 बोली खोलने की कियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए लियि समय और स्थान को बोली आमतंत्र में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियों निर्धारित समय पर खुले-आम खोलनी चाहिए। इस समय के बावजूद हुए बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोलीकार और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9. 3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, आयातक किसी भी बोली खोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9. 4 गुप्त रखी जाने वाली कियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बावजूद बोली से सम्बन्धित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से सम्बन्धित मिफारिशों के बारे में भी उस अपक्रिया को जो इन कियाविधियों से औपचारिक रूप से सम्बन्धित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9. 5 बोलियों की जांच

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज विलकुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित है और क्या बोलियों सामान्यता अवधारणा रूप से सही है, यदि बोलियों मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बावजूद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विमलेषण किया जाना चाहिए।

9. 6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएँ

पूर्व योग्यताओं की अनुसिद्धि में आयतक को चाहिए कि वह इस जात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रस्तुती रूप से चलाने के लिए अमर्ता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9. 7 बोलियों का मूल्यांकन और भिलास

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों परं शर्तों के प्रनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए संमजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बोली जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं संगताना या फालदू पूर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो ये बातें बोली वस्तावेजों में विशिष्ट-इत्तम मानदण्ड के प्रनुसार रूपए वेसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई संभवतया कीमत के लिए पूर्ण की घनराशि विचार में नहीं सी जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुग्न अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य आंका जाना है बोली स्वीकृत होने पर अप्पी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की धुलता अप्पी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनियम की दर सरकारी लोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुग्न के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खुलाने के बिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करने समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9. 8 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि अप्पी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करता चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियों प्राप्तित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक घनराशि द्वारा अनुसन्धित कीमत से अधिक हो जानी है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए तब अप्रैलिय देने चाहिए जहाँ (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आधार के अनुसार नहीं हैं या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अप्पी को चाहिए कि वह उम कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करें जिससे अस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पर्यवस्तुओं की धनराशि पर (या दोनों पर) विचार करें। विशेष परिस्थितियों में तिथि पर विचार करने के आव अप्पी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या वो बोलीकारों के राश सीदा कर सकता है।

9. 9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उसे बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निरिचित की गई है और जो असता और वित्तीय साथों के उपरिक्त मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पर्यवस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिसेंदारी से।

अनुबन्ध- 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं० तिं०

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई बिल्डी-110001

विषय :—येन ब्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से का आयात।

महोवय,

अपर उल्लिखित येन ब्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन के आयात के संबंध में (बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (द) में सम्बद्ध सम्बूद्धार संबरक के नाम में साक्ष-पत्र खोलने के लिए दिया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए इस आपातो निम्नलिखित व्यापेर प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके क्या वह सीधे क्षय या ग्रोप-बारिक खुले भन्तरीब्दीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय हो तो उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्तुत के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(ख) यदि कोई हो, तो पात्र से इतर लोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो, तो भारतीय एजेंट के कमीशन की घनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) सम्बूद्धार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ट) सम्बूद्धार के संभरक का नाम और पता :—

(१) राष्ट्रियका

(२) पात्र लोत देशों के राष्ट्रियकों द्वारा लिए गए शेयरों का प्रतिशत

(३) प्रतिनिधि की राष्ट्रियता और/ या संभरक का निवास स्थान

(४) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र लोत देशों के राष्ट्रिय हैं।

(ठ) वे भुगतान गते और संभावित तिथि जिसको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) मुश्किली को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ঢ) भारतीय बैंक दोक्यों को भुगतान करते समय किए जाने वाले उल्लेख (प्रत्येक सेट की संख्या उनका निपटान दिखाते हुए)

(ग) पोनलदान अनुदेश आहनास्तरण/पार्टिशिपमेन्ट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ।

(ह) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(ग) क्या उसी साइरेस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हाँ, तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संवर्ध जिसके अन्तर्गत आई०सी० एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है ।

यह प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा ।

भ्रवीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में ।

2. आयातक के बैंक । उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो आंच के दस्तावेज प्राप्त करने पर विवेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना सं०-८ आई०टी० सी० (पी०एन०) /७६, दिनांक १७-१-७६ या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूची समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रबलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक को सौमि गए आयात दस्तावेजों के मूल सेट से पहले ये निक्षेप जमा कर दिए गए हैं ।

वे धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई विल्सी या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, विल्सी में जमा करनी चाहिए । इस संबंध में आपका व्यात सार्वजनिक सूचना सं०-१४ आई०टी०सी० (पी०एन०) /६८, दिनांक ३०-८-६८, सं०-२३३ आई०टी०सी० (पी०एन०) /६८ दिनांक २४-१०-६८, संख्या-१३२ आई०टी०सी० (पी०एन०) /७१, दिनांक ५-१०-७१, सं० ७४-आई०टी०सी० (पी०एन०) /७४, दिनांक ३१-५-७४ और संख्या -१०३ आई०टी०सी० (पी०एन०) /७६, दिनांक १२-१०-७६ की शर्तों की ओर विलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह 'के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिंज २४३ मिलियन डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्रा एवाई परचेजिस अन्डर क्रेडिट लोन एसीएन्ट १९८०-८१ के लिए ९.४ विलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) से० आई०टी०सी०-१२ केरि गवर्नरेंट आफ जापान से आए हैं ।

जिन मामलों में तुल्य रूपाया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई विल्सी या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-१३२ आई०टी०सी० (पी०एन०) /७१, दिनांक ५-१०-७१ के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परिक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, य० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई विल्सी-११०००१.

जिन मामलों में तुल्य रूपाया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सं० दिनांक २४-१०-६८ में यथा उल्लिखित दरानी हुई द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रूपाया का पूरा व्यापार इस विभाग की भीजना चाहिए ।

यदि कोई ही तो, बैंक के खर्च, व्यापार और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अध्य खर्च (जिसमें विवेशी संभरकों के बैंकरों के खर्च भी शामिल है) प्रमुख लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई विल्सी को समतुल्य रूपए ग्राह करने पर ही तथ किए जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा उचित सलाह बैंक आफ इंडिया, टोकियो/भारतीय द्वातावास जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी ।

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) आण करार सं०-..... के अधीन आयात नाश-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय भ्रातृदेव,

आपके बैंक के साथ २५-३-१९८० को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एसद्वारा यथा संलग्न व्यारे के अनुसार सर्वश्री के नाम में येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक माखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, आई०सी० एफ० एक भारतीय द्वातावास, टोकियो और हमें पूळकित की जाए ।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आप की निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद आ० ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिवृत्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरकों को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और आ० ई० सी० एफ० एक द्वारा उसकी प्रतिवृत्ति की तिथि से दोनों के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय द्वातावास टोकियो द्वारा सीधे ही व्याज दिया जाएगा । बैंकों के अन्य खर्च जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल हैं क्यों कि वे भी परकार्य दस्तावेजों के संबंधान से संबंधित हैं और यह कोई ही तो, विवेशी संभरकों के बैंकरों के खर्च भी विवेशी संभरकों को ही देने पड़ते और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिवृत्ति का दावा आ० ई० सी० एफ० में नहीं किया जा सकता ।

यह प्राधिकार पत्र सम्ब्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकारण के महे खाले गए आगे के नए साख-पत्रों में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा ।

प्रिय महोदय,

इस आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण और मूल्य के लिए, लालकारी ड्राफ्ट एंड साइट डारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने प्रपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० बोल दिया है जो येन (येन महले) की कुल ब्लॉक ब्लॉकिंग से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा और परियोजना) से सम्बन्धित वस्तावेजों को नामी करना है सौदा तथ करने के लिए ड्राफ्ट से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सभी ड्राफ्ट और वस्तावेज प्रपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० विनाक के अन्तर्गत भुगता लिए गए हैं, से विविहत होने चाहिए ।

यह कोडिट हस्तांतरणीय नहीं है ।

हम एतद्वारा बताने वें हैं कि इस कोडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुसालन करके भुगता गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आवेदिती को वस्तावेजों की सुपुर्दी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारूर्धक बताया न जाए यह कोडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंट्स" कोडिट (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल बैंकर और फाक कामर, प्रमिकेशन नं० 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :—

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (अंग्री और इसके मनोनीत अधिकारी) डारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण को प्राप्ति के पश्चात इस कोडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट निवारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतान के भास्तु में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बाजे लालकारी विवरण की प्रावधानता है ।

2. ऊपर उल्लिखित छठे समझौते के अधीन जारी किए गए बदल बदला पत्र के उपवर्त्यों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से इपने भुगतानों के लिए प्रतिरूपि प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की बनराधि का भोल-तोल करने वाले बैंक डारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रवित करने का बदल देते हैं ।

3. उपर्युक्त मध्य 1 में यथा उल्लिखित वस्तावेज की एक प्रति और मसीधे में उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे ।

4. इस साथ के अन्तर्गत बैंक के सभी बच्चे प्रायातक/संभरक के लिए के लिए हैं ।

भवदीय,

(.....)

(वाणिज्यिक बैंक)

डारा

(प्रारिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साक्षरता सं० का एक अधिक चंग है ।

1. प्रारम्भिक भुगतान

संवादाधि : येन

कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है ।

अपेक्षित वस्तावेज़ : लालकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि ।

2. भुगतान कृदि

सम्पूर्ण योग की धरमाधि : येन
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—
देय अन्तिम अन्तिम भुगतान तिथि

पहली किस्त येन
दूसरी किस्त येन
.....

अपेक्षित वस्तावेज़ : (अंग्री अधबा उसके मनोनीत प्राधिकारी) डारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति विस्तार एक प्रपत्र संलग्न है ।

निष्पादन का विवरण

विनाक
संवर्ध
.....

सेवा में,

(संभरक का नाम और पता)

संवर्ध कहन करार सं० के अन्तर्गत परियोजना से सम्बन्धित के नाम में येन के लिए डारा जारी किए गए साख-पत्र की सं० विनाक और अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (अंग्री) एतद्वारा और के बीच समझौता सं० विनाक में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण प्रार्थिक सहायता निधि डारा की धनराधि (..... येन के बाद) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता है ।

(.....)
(अंग्री)

डारा

(प्रारिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा ।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 10-ITC (PN)82

New Delhi, the 24th February, 1982

Import Trade Control

Sub :—Licensing conditions for import of goods and services under the OECF loan agreements No. ID-P. 11 and I.D. P. 12 (Telecommunications Projects Nos. III and IV)

File No. IPC/23/(26)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licence in respect of goods and services under the Yen Credit of 5.0 Billion and Yen 9.4 Billion of the OECF Loan Agreement No. ID-P. 11 and ID-P. 12 for financing the import requirements of the Telecommunications Projects Nos. III and IV of the DGP&T as given in Appendices I & II respectively to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

APPENDIX I

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF Y 5.0 BILLION FOR TELECOMMUNICATIONS PROJECT (III), EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN

Section 1—General Conditions :

I. (i) The Yen Credit of Y 5.0 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTID/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 5,600 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78, ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 11". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to D.G. P&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on *CIF basis*.

I (iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 5,600 million (CIF) as specified at (i) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-85. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-85.

Section-II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In all circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency.

The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However prior approval of the Fund shall be obtained, if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement method(s) signed by duly authorised person together with its reasoning.

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its prior approval. The above documents/application may be forwarded, in duplicate, to the DEA (Japan Section) for obtaining approval of OECF.

II(iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 11 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(iv) Only one contract should be entered into against the import licence in exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(v) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Declaration in Contract.—The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty percent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty} \times 100}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (Name of company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II (vii) Permissible imports from non-eligible source countries—Financing of goods which contain materials originating from a non eligible source country or countries may be made provided that the imported portion is less than thirty percent (30 per cent) on an item by item basis in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}}$$

Section III.—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th Oct, 81 concerning the Yen Credit No. ID-11 (Project Aid) for Telecommunications Project (III) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No ID-P. 11 dated 15th Oct., 81; between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contracts duly signed by both DGP&T and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas suppliers or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P. 11 (Project Aid) for Telecommunication Project (III).

Section V—Payment to the overseas suppliers — Letters of Credit procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would *ipso facto* apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V. (iv) All charges on account of opening, maintenance, and on the operation of the letter of Credit will be to the account of overseas suppliers. Bank of India Tokyo will therefore recover all these charges from the suppliers. Bank charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (Mo Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest-payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department (Vide section VI (iv) infra)

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the nego-

table shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&F or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad-Purchase under credits/Loan Agreements/Loans from the Government of Japan—5.0 billion Yen Credit No. ID-11 for Telecommunications Project (III)." The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)68 dated 30-8-1968, No. 233. ITC(PN)68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC (PN)74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority if any" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans:—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI (i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII—Miscellaneous provisions

VII (i) *Reports on the utilisation of the import licence*
The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment" Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII (iv) Future Instructions

The license shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P 11 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII (vi) List of Annexures

Annexure-I List of eligible source countries

Annexure-II Main Guidelines for Procurement.

Annexure-III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-IV Form of Letter of Authority.

Annexure-V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure-VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services)

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomey

III. AMERICA, North and Central	
Bahamas	
Barbados	
Belize	
Bermuda	
Costa Rica	
Cuba	
Dominican Republic	
El Salvador	
Guadeloupe	
Guatemala	
Haiti	
Honduras	
Jamaica	
Martinique	
Mexico	
Netherlands Antilles	
Nicaragua	
Panama	
St. Pierre & Miquelon	
Trinidad and Tobago	
West Indies (Br.) n.i.e.	
(a) Associated States (4)	
(b) Dependencies (5)	
(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.	
(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.	
(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustatius, St. Martin (Southern part).	
(4) Main Islands: Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.	
(5) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.	

IV. AMERICA, South	
Argentina	
Bolivia	
Brazil	
Chile	
Colombia	
Falkland Islands	
French Guiana	
Guyana	
Paraguay	
Peru	
Surinam	
Uruguay	
V. ASIA, Middle East	
Bahrain	
Israel	
Jordan	
Lebanon	
Oman	
Syrian Arab Republic	
United Arab Emirates (6)	
Yemen Arab Republic	
Yemen, People's D.R. (7)	
VI. ASIA, South	
Afghanistan	
Bangladesh	
Bhutan	
Burma	
India	
Maldives	
Nepal	
Pakistan	
Sri Lanka	
VII. ASIA, Far East	
Brunei	
Hong Kong	
Khmer Republic	
Korea, Republic of	
Laos	
Macao	
Malaysia	
Philippines	
Singapore	
Taiwan	
Thailand	
Timor	
Viet-Nam, Rep. of	
Viet-Nam Dem. Rep.	
VIII. OCEANIA	
Cook Islands	
Fiji	
Gilbert & Ellice Is.	
French Polynesia (8)	
Nauru	
New Calendonia	
New Hebrides (Br. and Fr.)	
Niue	
Pacific Islands (US) (9)	
Papua New Guinea	
Solomon Islands (Br.)	
Tonga	
Wallis and Futuna	
Western Samoa	
(6) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.	
(7) Including Aden and various sultanates and emirates.	
(8) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.	
(9) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Island, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam)	

IX. Europe
 Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC

Algeria
 Bolivia
 Libyan Arab Republic
 Gabon
 Nigeria
 Ecuador
 Venezuela
 Iran
 Iraq
 Kuwait
 Qatar
 Saudi Arabia
 Abu Dhabi
 Indonesia

ANNEXURE II

Main Guidelines for Procurement of Goods and Services
 Under the Project Loan as Formulated by O.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts.

II-1. Bid Bonds or Guarantees.

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantee should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract.

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract.

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts")

are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers.

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as ("the eligible supplier")) shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price.

- (a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is a eligible supplier, as _____ per cent (_____ per cent) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent (_____) of the directors are nationals _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards :—If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names :—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :—Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. That subject of the guarantee of bond required should be defined with the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage :—Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure :—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract.)

VII. Settlement of Disputes :—Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation :—Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids :—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures :—The date, hour and place for the latest received of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alteration of Bids :—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder

for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance of the price of his bid.

IX-4. Procedures to the confidential :—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids :—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders :—In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids :—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates of the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids :—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bid may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (for amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract :—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
 Ministry of Finance,
 Department of Economic Affairs,
 U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
 Parliament Street,
 New Delhi-110001.

Sub : Import of from Japan under the
 Yen Credit No. (Project Aid)

Sir,

In connection with the import of from under the above mentioned Yen Credit No. (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the overseas supplier :
 - (l) Nationality
 - (m) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries.
 - (n) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
 - (o) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (p) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (q) Expected date of completion of deliveries.
- (r) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (s) Shipment instructions (Indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (t) Name and address of the importer's bank in India.
- (u) Whether a contract (s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India
 Ministry of Finance
 Department of Economic Affairs
 New Delhi, the

To

The Bank of India,
 Tokyo Branch,
 Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan
 Agreement No. —Issue of Letter of
 Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen favouring M/s. as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto _____.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer with reference to their letter No. dated _____.

2. Importers' Banker They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the Importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited as 'K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad under Purchases under Credit Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—5.0 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. II for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V
Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date :

To

(Name and address of the Supplier)

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____ dated _____

Between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding any aggregate amount of Y. _____ (Say Yen _____) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in _____ Full set of clean on board ocean bills of lading made out

to order and blank endorsed and marked 'Freight and "Notify _____":
Other documents.

Evidencing shipment of (brief description of goods) to be shipped referring to Contract No. _____ (if any) from _____ to _____
Partial shipments are _____ permitted.

Transhipment is _____ permitted.
Bills of lading must be dated not later than Draft must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under _____, dated _____ and Import Reference No. (s). (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credit" (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating Bank.

2. The negotiating Bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____.

3. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount Y _____
being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y _____
being _____ % of of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount Y _____
being _____ % of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI
Form OECF-LC IIIrrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

Date :

To _____

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (Say Yen _____) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____.

All drafts and documents must be marked "Drawn under Irrevocable credit No. _____ dated _____."

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt therefor.

4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorized signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount Y _____
being _____ % of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount Y _____
being _____ % of the total contract price to be paid as follows :

Amount due _____ Latest presentation date _____

1st Instalment Y _____

2nd Instalment Y _____

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :
Ref. No. _____

To _____

(Name and address of the supplier)

Re: Letter of Credit No. _____, dated _____, issued by _____ for Y _____ in favour of _____ concerning _____ Project under Loan Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of Y _____ (Yen _____ only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____, dated _____ between _____ and _____

(Borrower)

By :
(Authorized Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

APPENDIX II

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF Y. 9.4 BILLION FOR TELECOMMUNICATIONS PROJECT (IV) EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN

Section I : General Conditions

1(i) The Yen Credit of 9.4 billion Yen extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications project of the DGP & T is used in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured

under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 10,500 million, (CIF).

The Rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI & E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to DGP&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF Basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T, more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 10,500 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-1985. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Import to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in Indian rupees. 'Firm orders' means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas supplies and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility

of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

..... Months after the receipt of letter of credit but to be completed latest by the end of

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1985.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The board guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. Normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering. However, prior approval of the Fund shall be obtained, if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund on application for approval of procurement method(s) signed by duly authorised person together with its reasoning, through the Department of Economic Affairs (Japan Section).

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its prior approval, through the Department of Economic Affairs (Japan Section).

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P12 for 1980-81 the details of which are given in Section VI below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier :

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Declaration in Contract :

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :—

Imported CIF Price + Import Duty $\times 100$ "

Supplier's FOB Price

and

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (Name of company) has been incorporated and registered in _____

—(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II (vii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formula;

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100\%$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P12 (Project Aid) for Telecommunications Project (IV) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P12 dated 15th October, 81 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF.

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P12 (Project Aid) for Telecommunication Project (IV).

Section V—Payment to the Overseas Suppliers—Letter of Credit procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importers Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letter of credit on the basis of the letter of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of Credit will be to the account of Overseas Suppliers. Bank of India, Tokyo will, therefore, recover all these charges from the Suppliers' Bank, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the date of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (MoF) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India, in Japan will be recovered from the P&T Department (Vide Section VI(iv) infra).

Section VI—Responsibility for rupee deposit.

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)74 dt. 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupees deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreement; Loans from the Government of Japan—9.4 billion Yen Credit No. ID-P12 for Telecommunications Project (IV)." The provisions regarding calculation and deposit for interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filing in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India, should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DPA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charged etc., made by Embassy of India, Tokyo, to the BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII—Miscellaneous provisions.

VII (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.12 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VII (v) Breach of violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII (vi) List of Annexures

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—Broad Guidelines for Procurement.

Annexure III—Request for issue of Letter of Authority.

Annexure IV—Form of Letter of Authority.

Annexure V—Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports.)

Annexure VI—Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Agypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verds Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia

Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, inclu the island of Fernando Po.

St. Helena and dep. (1)
 Sao Tomo and Principle
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Swaziland
 Terro. Afars and Issar
 Togo
 Uganda
 Un. Rep. of Tanzania
 Upper Volta
 Zaire Republic
 Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
 Barbados
 Belize
 Bermula
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tobago

West Indies (Br.) n. i.e.

(a) Associated States (3)
 (b) Dependecies (4)

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Falkland Islands
 French Gulana
 Guyana
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay

(1) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
 (2) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).
 (3) Main islands: Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Carristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
 (4) Main islands: Montserrat, Cayman, Turkas and Calcos, and British Virgin Islands.

V. ASIA, Middle East
 Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Emirates (5)
 Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D.R. (6)

VI. ASIA, South

Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldivis
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of Laos
 Macao
 Mafaysia
 Phillipines
 Singapore
 Taiwan
 Tailand
 Timor
 Viet-nam, Rep. of
 Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Coek Islands
 Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (7)
 Nauru
 New Calendonia
 New Hebrices (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (8)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

XI. Europe

Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(5) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
 (6) Including Aden and various sultanates and emirates.
 (7) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
 (8) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Mariana Islands (except Guam).

(a2) Members or Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

(3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ per cent (____%) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent (____%) of the directors are nationals _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of

ANNEXURE II
Main Guidelines for Procurement of Goods and Services Under The Project Loan as Formulated by Q.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are as usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Condition of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are certified to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions :

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.
- (2) a majority of full time directors shall be nationals of the eligible source countries and

which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract.)

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alteration of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsible bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated

bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

Request For Issue of the Letter of Authority

No.:

Date:

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject.—Import of
Yen Credit No. _____ from Japan under the
(Project Aid).

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned Yen Credit No. _____ (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the overseas supplier :
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject.—Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan
Agreement No. _____ Issue of Letter of
Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25th March, 1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ favouring M/s. _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers, if any, are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto _____.

ANNEXURE V

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____

2. Importer's Banker _____ They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc., abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—94 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 12 for 1980-81."

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, on the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

Form OECF-LC 1

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date :

To _____

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____ between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen _____) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and "Notify"

Other documents.

Evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ (if any) from _____ to _____ Partial shipments are _____ permitted. Transhipment is _____ permitted.

Bills of lading must be dated not later than _____ Draft must be presented for negotiation not later than _____

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under _____ irrevocable credit No. _____, dated _____ and Import Reference No(s). _____ (if any)."

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____.

3. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitute an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y _____
being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : Y _____
being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI

FORM OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

To _____

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen _____) available by beneficiary's drafts at sight for full statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated _____".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By _____

(Authorised Signature)

Payment Schedule

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being _____ % of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Y _____
being _____ % of the total contract price
to be paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
------------	--------------------------

Ist Instalment : Y _____

2nd Instalment : Y _____

.....

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To

(Name and address of the supplier)

Re : Letter of Credit No. _____, dated _____, issued by _____ for Y _____ in favour of _____ concerning _____ Project under Loan Agreement No. _____

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of Y _____ (Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____, dated _____ between _____ and _____

(Borrower)

By : _____
(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.